गरवी गुजरात

TITLE CODE:- UPHIN51504

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 227
दि. 18.12.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

भारत, ओमान बृहस्पतिवार को मस्कट में मुक्त व्यापार समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर

(जीएनएस)।

नयी दिल्ली. भारत और ओमान आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मस्कट में मुक्त व्यापार समझौते पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर करेंगे. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा पर हैं. मोदी मंगलवार को जॉर्डन से इथियोपिया पहुंचे और अदीस अबाबा से ओमान के लिए रवाना होंगे.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मस्कट पहुंच चुके हैं. मुक्त व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) कहा जाता है. इस पर बातचीत औपचारिक

रूप से नवंबर 2023 में शुरू हुई जो इस वर्ष संपन्न हो गई. इस प्रकार के समझौते में दो व्यापारिक साझेदार अपने बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को काफी हद तक कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं. वे सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील भी देते हैं.

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में ओमान भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है. इस बीच, मस्कट में ओमान-भारत व्यापार मंच को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि दोनों देशों के दलों ने समझौते को अंतिम रूप देने के लिए काफी प्रयास किए हैं.

उन्होंने बताया कि ओमान करीब 20 वर्ष के अंतराल के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है. देश ने आखिरी बार जनवरी 2006 में अमेरिका के साथ इसी तरह का समझौता किया था.

गोयल ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा, 'मुक्त व्यापार समझौता आप सभी के लिए अपार अवसर लाता है.' उन्होंने कहा कि वस्त्र, जूते, मोटर वाहन व उसके कलपुर्जे, रत्न एवं आभूषण, कृषि रसायन तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं. मंत्री ने कहा कि ओमान अन्य जीसीसी देशों अफ्रीका एवं मध्य एशिया के लिए एक प्रवेश द्वार है.

उन्होंने कहा, ' हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, अनुसंधान एवं विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे सेवा क्षेत्रों में सहयोग पर विचार कर सकते हैं.' गोयल ने कहा कि सहयोग के चार प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा बदलाव, अवसंरचना विकास, खाद्य सुरक्षा और स्टार्टअप हैं. भारत का पहले से ही जीसीसी के एक अन्य सदस्य देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ इसी तरह का समझौता है जो मई 2022 में लागू हुआ था. जीसीसी के अन्य सदस्य बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और कतर हैं. भारत और कतर भी जल्द ही व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करेंगे.

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-ओमान का द्विपक्षीय व्यापार करीब 10.5 अरब अमेरिकी डॉलर (निर्यात चार अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 6.54 अरब अमेरिकी डॉलर) था. भारत के प्रमुख आयात पेट्रोलियम उत्पाद और यूरिया हैं जिनकी कुल आयात में हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है. अन्य प्रमुख उत्पादों में प्रोपलीन और एथिलीन पॉलिमर, पेट कोक, जिप्सम, रसायन, लोहा और इस्पात तथा अपरिष्कृत एल्युमीनियम शामिल हैं. ओमान को निर्यात की जाने वाली मुख्य भारतीय वस्तुओं में खनिज ईंधन, रसायन, बहुमूल्य धातुएं, लोहा व इस्पात, अनाज, जहाज, नावें, विद्युत मशीनरी, बॉयलर, चाय, कॉफी, मसाले, वस्त्र और खाद्य पदार्थ शामिल हैं.

यूपी के आत्मविश्वास का कारण कानून का राज, प्रदेश की छवि बदली : सीएम

लखनऊ (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पीएसी के स्थापना दिवस के अवसर पर पीएसी जवानों को संबोधित किया और बीते साढ़े आठ साल में पीएसी को और बेहतर बनाने के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 78 वर्ष से पीएसी बल का इतिहास अनुशासन, शौर्य, त्याग व समर्पण का रहा है। उन्होंने जवानों से अपील की कि साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, व्यावसायिक दक्षता व कठिन प्रशिक्षण ही आपकी पहचान बननी चाहिए। सरकार आश्वस्त करती है कि आपके सम्मान व सरकार के स्तर पर मिलने वाली सुविधा-संसाधन में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। यूपी के अंदर आत्मविश्वास का प्रमुख कारण कानून का राज है।

कानून का राज सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही सुशासन की गारंटी दे सकता है। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएसी के स्थापना दिवस समारोह-2025 का शुभारंभ किया। सीएम ने पीएसी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन किया। सीएम ने 78वर्ष के गौरवशाली

इतिहास के लिए पीएसी बल को बधाई दी।

संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर कार्य करता है पीएसी बल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पीएसी बल आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, प्रदेश में महत्वपूर्ण त्योहारों, अतिविशिष्ट महानुभावों के आगमन, लोकतंत्र के महापर्व ह्यचुनावह्ण को शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के साथ ही संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर कार्य करता है। पीएसी के अधिकारी व कार्मिक विभिन्न आयामों के माध्यम से न सिर्फ यूपी, बल्कि देश के अंदर यूपी पीएसी बल, एसएसएफ, यातायात पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक ड्यूटी, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक, एटीएस व एसटीएफ कमांडो के रूप में सेवाएं प्रदान कर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

सीएम योगी ने पीएसी के अदम्य साहस को भी गिनाया

सीएम योगी ने पीएसी बल के अदम्य साहस की चर्चा की। बताया कि 30वीं वाहिनी पीएसी के जवानों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले का जवाब दिया और पांचों आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 में श्रीराम जन्मभूमि परिसर अयोध्या में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने सभी आतंकियों को मार गिराया गया था।

सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने पीएसी की 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए यूपी के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखा और आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से यूपी की बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में सफलता हासिल की।

राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया।

इस शिखर सम्मेलन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए

जिन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई, उनमें पर्यटन एवं आतिथ्य, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध क्षेत्र, वस्त्र, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास, आईटी/आईटीईएस, मनोरंजन एवं खेल, अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स, तथा ऊर्जा शामिल हैं।

गुरु तेग बहादुर जी असहिष्णुता के युग में उत्पीड़ितों के लिए ढाल बनकर खड़े रहेः उपराष्ट्रपति

- श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350 वें शहीदी दिवस की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित अंतरधार्मिक सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने वैश्विक शांति और धार्मिक सद्भाव का आ'ान किया।
- गुरु तेग बहादुर जी को न केवल एक सिख गुरु के रूप में, बल्कि सर्वोच्च बलिदान और नैतिक साहस के सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में पूजा जाता हैः उपराष्ट्रपति
- गुरु तेग बहादुर जी असहिष्णुता के युग में उत्पीड़ितों के लिए ढाल बनकर खड़े रहेः उपराष्ट्रपति
- भारत जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत करके विश्व का नेतृत्व कर रहा हैः उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री ने उपनिषद के आदर्श 'वसुधैव कुटुंबकम' को वैश्विक आवाज दी; भारत का जी20 विषय 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' भारत की सभ्यतागत बुद्धिमत्ता को दर्शाता हैः उपराष्ट्रपति
- एक भारत, श्रेष्ठ भारत भारत की सभ्यतागत आत्मा को दर्शाता हैः उपराष्ट्रपति

(जीएनएस)।

भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक अंतरधार्मिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में भाग लेना अत्यंत सम्मान की बात है और इसे शांति, मानवाधिकार और धार्मिक सद्भाव के लिए एक वैश्विक आ'ान बताया।

उपराष्ट्रपति ने गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ पर गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपनी यात्रा को याद किया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को नैतिक साहस का प्रतीक बताया, जिनका जीवन और बलिदान समस्त मानवता के लिए है।

उपराष्ट्रपति ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का वर्णन करते हुए कहा कि यह धार्मिक स्वतंत्रता की ऐतिहासिक पुष्टि में से एक है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने राजनीतिक सत्ता या किसी एक धर्म की श्रेष्ठता के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तियों के अपने अंतरात्मा के अनुसार जीने और पूजा करने के अधिकार की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि असहिष्णुता के दौर में वे उत्पीड़ितों के रक्षक बनकर खड़े रहे।

श्री सीपी राधाकृष्णन ने शाश्वत प्रासंगिकता को उजागर करते हुए गुरु तेग बहादुर जी के संदेश में कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने विश्व को यह शिक्षा दी कि करुणा से प्रेरित साहस समाजों को रूपांतरित कर सकता है, और अन्याय के सामने मौन रहना सच्चे विश्वास के विपरीत है। उन्होंने कहा कि इन्हीं मूल्यों के कारण गुरु तेग बहादुर जी को न केवल एक सिख गुरु के रूप में, बल्कि सर्वोच्च बलिदान और नैतिक साहस के सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में पूजा जाता है और उन्हें 'हिंद दी चादर' की उपाधि से सम्मानित किया गया है।

लोकसभा में चली बहस में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि शांति विधेयक में मजबूत सुरक्षा और दायित्व से जुड़े सुरक्षात्मक उपाय कायम हैं

- शांति विधेयक के मूल में परमाणु नियामक के लिए वैधानिक दर्जा और दायित्व संबंधी अद्यतन ढांचा हैः डॉ. जितेंद्र सिंह
- केन्द्रीय मंत्री ने लोकसभा को बताया कि भारत के 2047 के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निजी भागीदारी आवश्यक है
- लोकसभा ने शांति विधेयक पर केन्द्रीय मंत्री का विस्तृत जवाब सुना, जिसमें सुरक्षा, जवाबदेही और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों पर जोर दिया गया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में स्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांस्डमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विधेयक, 2025 पर हुई बहस का जवाब देते हुए सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान किया और एक व्यापक नए परमाणु कानून को पेश करने

के पीछे सरकार के तर्क को स्पष्ट किया। सभी दलों द्वारा उठाये गए मुद्दों का जवाब देते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह विधेयक समकालीन तकनीकी, आर्थिक और ऊर्जा संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप भारत के परमाणु ढांचे का आधुनिकीकरण करेगा और साथ ही 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम के बाद से लागू मूलभूत सुरक्षा, संरक्षा एवं नियामक संबंधी उपायों को बनाए रखते हुए उन्हें मजबूत भी करेगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित कानून मौजूदा कानूनों को सुदृढ़ करता है और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, जो अब तक कार्यकारी आदेश के माध्यम से कार्य करता था, को वैधानिक दर्जा देकर नियामक ढांचे को उन्नत बनाता है।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सुरक्षा संबंधी मानदंड, विखंडनीय पदार्थ, प्रयुक्त ईंधन और भारी जल पर सुरक्षा नियंत्रण एवं आवधिक निरीक्षण निजी भागीदारी के बावजूद सरकार की पूर्ण निगरानी में रहेंगे। केन्द्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि निजी संस्थाओं का संवेदनशील पदार्थों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा और प्रयुक्त ईंधन का प्रबंधन दशकों से चली आ रही प्रणाली के अनुसार सरकार द्वारा ही किया जाता रहेगा।

52,400 आगंतुकों के साथ खिजड़िया ने मजबूत की गुजरात की इको-टूरिज्म पहचान

- वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में गुजरात की इकोलॉजिकल उत्कृष्टता के बेजोड़ उदाहरण के रूप में उभरेगा खिजड़िया पक्षी अभयारण्य
- रामसर साइट के दर्जे के साथ खिजड़िया अभयारण्य गुजरात के टिकाऊ विकास का जीवंत उदाहरण

गांधीनगर, 17 दिसंबर : खिजड़िया पक्षी अभयारण्य ने वर्ष 2024-25 के दौरान 52,400 से अधिक सैलानियों को आकर्षित कर इको-टूरिज्म क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान को मजबूत किया है। राज्य में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तब यह अभयारण्य पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) उत्कृष्टता और टिकाऊ विकास के प्रति गुजरात की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बन रहा है।

वीजीआरसी 2026 से पहले, जामनगर के निकट स्थित खिजड़िया रामसर स्थल गुजरात के महत्वपूर्ण पाकृतिक लैंडमार्क के रूप में उभरकर सामने आया है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र आज राज्य के अग्रणी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं, जहां प्राकृतिक लैंडस्कैप, वन्यजीवन, तटीय सुंदरता, आध्यात्मिक स्थलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनोखा

संगम देखने को मिलता है। सफेद रण से लेकर सौराष्ट्र के तीर्थ स्थलों, समुद्र तट और अभयारण्यों तक की यात्रा पर्यटकों को विविधतापूर्ण और यादगार अनुभव देती है।

600 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला खिजड़िया पक्षी अभयारण्य मीठे और खारे पानी के दुर्लभ संगम के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह अनोखा पारिस्थितिक तंत्र पक्षियों के लिए एक विविधतापूर्ण निवास उपलब्ध कराता है। गुजरात सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान यहां 317 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई थी, जो 2024-25 में बढ़कर 332 हो गई है, जो इस अभयारण्य की लगातार विकसित होती जैव विविधता का प्रमाण है।

इस पारिस्थितिक समृद्धि को 2022 में वैश्विक मान्यता मिली, जब खिजड़िया को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। राज्य सरकार यहां पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित कर रही है, जिसमें वॉच टावर, वन-कुटीर, पक्षी निरीक्षण प्लेटफॉर्म, इंटरप्रिटेशन सेंटर, सेल्फी पॉइंट और जानकारी देने वाले साइन बोर्ड शामिल हैं।

अभयारण्य की मुख्य ताकत इसके विविधतापूर्ण और सुरक्षित आवास स्थल में है, जहां मीठे पानी का बहाव समुद्री ज्वार के साथ मिलता है, और तटबंधों एवं खंदकों के नेटवर्क से यह और भी समृद्ध हो जाता है, जो वन्यजीवों के लिए आदर्श माइक्रोहैबिटेट यानी सूक्ष्म आवास बनाते हैं। ये सुविधाएं खिजड़िया को भारत के सबसे जीवंत पक्षी स्थलों में से एक बनाती हैं। साथ ही, यह आर्द्रभूमि (वेटलैंड) संरक्षण के प्रति गुजरात के वैज्ञानिक और योजनाबद्ध दृष्टिकोण को भी मजबूत बनाती है।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

सम्पादकीय

जान की परवाह किए बिना हिम्मत से किया आतंकी पर काबू

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को जश्न मना रहे बान्डी बीच पर लोगों पर दो आतंकियों ने हमला कर दिया। इस दौरान 44 साल के अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों से भिड़ गया और कई जानें बचाईं। हुआ यूं कि रविवार को सिडनी के बान्डी बीच पर यहूदियों के हनुक्का पर्व पर लोग पर्व का मजा उठा रहे थे। हनुक्का यहूदियों का सालाना त्यौहार है। इस दौरान दो बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी। गोलियों की आवाजें सुनकर बीच पर अफरा-तफरी मच गईं और लोग इधर-उधर भागने लगे। इस अंधाधुंध फायरिंग में अब तक 16 लोगों की मौत हो गईं और दर्जनों घायल हो गए। आतंकियों की निशानदेही हो चुकी है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले बाप और बेटे हैं, जिनमें से एक की तो मौके पर ही मौत हो गई। आस्ट्रेलिया जांच एजेंसियों ने आरोपी के बैकग्राउंड की जांच शुरू कर दी है। शूटिंग में शामिल पिता (50 वर्षीय) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका 25 वर्षीय बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भती है, सिडनी अटैक में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। आस्ट्रेलिया की जांच एजेंसियां इस घटना को लेकर बहुत गंभीर है। अहम बात यह भी है कि हमले में शामिल पिता-पुत्र की पहचान पाकिस्तानी मूल के रूप में हुई है। वहीं अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने भी दोनों आतंकियों को पाकिस्तानी नागरिक बताया है। हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और सिडनी में रह रहे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि गोलीबारी के बाद पास ही एक सड़क पर एक कार से कई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लेसिव डिवाइस यानी विस्फोटक बरामद किए गए, जिससे आशंका है कि हमले की साजिश इससे काफी ज्यादा तबाही पैलाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने की थी। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी एसियो ने पुष्टि की है कि हमलावरों में से एक पहले से सुरक्षा एजेंसियों की नजर में संदिग्ध था, लेकिन उसे तत्काल खतरे के रूप में लिस्ट नहीं किया गया था। इधर दोनों आतंकी गोलियां बरसा रहे थे उधर 44 साल के अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना हिम्मत दिखाते हुए पीछे से आतंकी पर झपट्टा मारा और उससे बंदूक छीन ली, जिससे कई लोगों को सुरक्षित निकालने का मौका मिल गया। लोग अहमद अल अहमद को ऑस्ट्रेलिया का नया हीरो कह रहे हैं। अहमद जब आतंकी साजिद से मुठभेड़ करने जा रहा था, तब उनके भाई ने उन्हें रोका था। तब उन्होंने कहा था कि अगर मुझे वुछ हुआ तो परिवार को बताना कि मैं लोगों की जान बचाते हुए मारा गया। अहमद फल-सब्जी की दुकान चलाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले की निंदा हुई है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार से लेकर मुस्लिम-अरब देशों की ओर से भी आतंकवाद और हिंसा के सभी रूपों को खारिज किया है। मगर यह भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना और विरोध के बावजूद किसी समुदाय से नफरत की भावना में डूबे को रोक पाना एक मुश्किल चुनौती है। यह स्वाभाविक है कि इस आतंकी हमले की वैश्विक स्तर पर निंदा होगी और शोक-संवेदनाएं व्यक्त की जाएंगी, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। दुनिया भर में जिहादी आतंक का खतरा जिस तरह उभर रहा है उसका मुकाबला तभी किया जा सकता है जब पूरा विश्व समुदाय मिलकर इस उठते खतरे का ईमानदारी से सामना करे और मिलकर मुकाबला करने के लिए कदम उठाएं। बान्डी बीच के हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। दोनों ही आतंकी पाकिस्तानी मूल के निकले। यह किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान विश्व की सबसे बड़ी आतंकी पैक्ट्री है जहां साल दर साल हजारों आतंकी तैयार किए जाते हैं। भारत तो बार-बार इस बात को कहता रहता है पर दुनिया मानने को तैयार नहीं, पहलगाम हमला भी

स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए 'सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन' कार्यक्रम में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2800 करोड़ रुपए के चेक वितरण का गौरवशाली समारोह अहमदाबाद में आयोजित

■ उप मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री और शहरी विकास राज्य मंत्री की उपस्थिति

■ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

● श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने देश के समक्ष यह उदाहरण पेश किया कि दूरदर्शी नेतृत्व और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ यदि धन की कमी न हो, तो शहरी विकास कितनी तेजी से किया जा सकता है

● जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के विरुद्ध राज्य के शहरों ने ग्रीन स्पेस, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन मोबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छ सर्वेक्षण में लीड ली है

● विकास के कार्यों में गुणवत्ता और स्वच्छता को वरीयता दें

● 2035 में जब हम गुजरात की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तब तक राज्य के शहरों को देश में उत्कृष्ट सुविधा युक्त शहर बनाने का अवसर है

● श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात से जो विकास पथ शुरू किया था, उस पर आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

● सुनिश्चित करें कि सभी विकास कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके पूर्ण हों : शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई

गांधीनगर, 17 दिसंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए ह्यसिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेनह्न यानी नवाचार, एकीकरण और स्थिरता के लिए शहरी निवेश कार्यक्रम में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे शहरों और महानगरों ने ग्रीन स्पेस, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन मोबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता सर्वेक्षण में लीड ली है। इतना ही नहीं, सर्कुलर इकोनॉमी को गति देने के लिए चार ह्यआरह्न रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल और रिकवर पर फोकस किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2005 में शहरी विकास वर्ष की शुरूआत की थी, यह वह दौर था जब देश में शहरीकरण को एक चुनौती माना जाता था। उन्होंने हमारी विरासत के अनुरूप शहरी विकास मॉडल विकसित करने के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की मजबूत नींव रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में शहरी विकास वर्ष के जरिए इसका श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया है कि, यदि दूरदर्शी नेतृत्व हो और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ धन की कोई कमी न हो, तो शहरी विकास कितनी तेजी से किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि शहरी विकास वर्ष 2005 की दो दशकों की सफलता के चलते मॉडर्न अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी आधुनिक शहरी परिवर्तन में बड़ा बदलाव आया है। इस परिवर्तन को और अधिक गति देने के लिए राज्य सरकार ने सर्वस्पर्शी, सर्वपोषक और सर्वसमावेशी नगरों के विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया है।

मुख्यमंत्री ने शहरी विकास वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में बुधवार को अहमदाबाद आयोजित कार्यक्रम में राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं को सर्वांगीण विकास कार्यों के लिए एक साथ, एक ही मंच से कुल 2800 करोड़ रुपए राशि के चेक वितरित किए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई और राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला

की उपस्थिति में राज्य की 8 महानगर पालिकाओं को कुल 2132 करोड़ रुपए तथा नवगठित 9 महानगर पालिकाओं को 40-40 करोड़ रुपए के हिसाब से कुल 360 करोड़ रुपए की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों के लिए दी। इसके अलावा, राज्य की 152 नगर पालिकाओं को कुल 308 करोड़ रुपए सहित कुल मिलाकर 2800 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने ऐसा वित्तीय प्रबंधन किया है, जिसमें नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के आयोजन में धन की कोई कमी रहे। अब नगर पालिकाओं को लोगों के विकास कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन का उपयोग करने की क्षमता बढ़ानी होगी।

उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता और स्वच्छता को वरीयता देने का प्रेरक सुझाव देते हुए कहा कि स्वच्छता सभी का सहज स्वभाव बन गया है, ऐसे में नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं को चाहिए कि वे इस दिशा में और अधिक पहल करने का दायित्व निभाएं।

श्री पटेल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाने वाले राज्य के 6 शहरों का उल्लेख किया और उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सभी शहरों को लीड लेने और प्रत्येक वार्ड में कचरे का 100 फीसदी पृथक्करण करने के साथ ही नगर पालिकाओं में बिजली बिल की बचत के लिए हरित एवं स्वच्छ सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के निर्माण का रोडमैप ह्यअर्निंग वेल, लिविंग वेलह्न के संकल्प के साथ तैयार किया गया है। 2047 के विकसित भारत से पहले, जब 2035 में गुजरात की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, तब तक हमारे शहरों को देश में उत्कृष्ट सुविधा युक्त शहर बनाने का अवसर है।

उन्होंने महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया कि नागरिक-केंद्रित सेवाओं और मोबाइल गवर्नेंस का दायरा बढ़ाते हुए सभी शहरों में टैक्स कलेक्शन और बिजली बिल सहित सभी बिलों के भुगतान के लिए यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने इस मौके पर शहरी विकास के लिए एक ही स्थल से राज्य भर की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं को चेक वितरित करने के इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं और मुश्किलों के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्व और शहरी विकास के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने के लिए मुख्यमंत्री ने लगातार प्रयासरत रहते हुए जनकल्याण के अनेक कार्य पूर्ण कराए हैं। उन्हीं के कार्यकाल में स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के अनेक शहरों ने आगे बढ़कर देश में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन दशक पहले की सरकारों के दौर में लोगों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में निरंतर मुश्किलों के बीच जीना पड़ता था। लेकिन, श्री नरेन्द्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री शासन की कमान संभालने के बाद गुजरात के शहर और जिले लगातार विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़े हैं और आज पूरा देश विकास की इस तेज गति को देख रहा है।

उन्होंने उच्च स्तरीय ढांचागत सुविधाओं के साथ नगरों के सतत विकास की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य की 9 नगर पालिकाएं अब महानगर पालिका बन गई हैं। उन्होंने धोलेरा और गिफ्ट सिटी का उदाहरण देते हुए स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया।

शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात के विकास के लिए अनेक नए आयाम गढ़े और योजनाएं लागू कीं। उन्होंने ज्योतिग्राम योजना, शाला प्रवेशोत्सव और वाइब्रेंट गुजरात जैसी योजनाओं और अभियानों के अलावा आदिवासी विकास के लिए अलग से बजट आवंटन तथा 2009-10 में स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना शुरू की थी।

श्री देसाई ने कहा कि उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शहरी विकास विभाग का बजट 22,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया है। शहरों में सड़क, सैनिटेशन, ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर सहित शहरी विकास की अन्य परियोजनाओं के लिए शहरी विकास विभाग लगातार काम कर रहा है। उन्होंने सभी महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के पदाधिकारियों से सभी विकास कार्यों को समय पर पूरा करने पर बल दिया।

शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला ने स्वागत भाषण में कहा कि राज्य सरकार महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सदैव कटिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के सर्वांगीण विकास की लगातार चिंता की थी। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी शहरी विकास विभाग के बजट में लगातार बढ़ोतरी कर लोगों की सुख-सुविधा बढ़ाने और अनेक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।

इस अवसर पर राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की झलक दिखाने वाली लघु फिल्म भी दिखाई गई।

कार्यक्रम में विधानसभा के उप मुख्य सचेतक श्री जगदीशभाई मकवाणा, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, स्थानीय विधायक, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री एम. थेन्नारसन, कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज श्रीमती रेम्या मोहन, म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड की अपर आयुक्त श्रीमती वीमा पटेल सहित राज्य भर की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे।

पिछले 5 वर्षों के दौरान इसरो द्वारा कुल 22 उपग्रह प्रक्षेपित

(जीएनएस)।

इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन

पिछले 5 वर्षों (दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025) के दौरान इसरो द्वारा कुल 22 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। इनमें से 7 पृथ्वी अवलोकन, 4 संचार, 2 नेविगेशन, 3 अंतरिक्ष विज्ञान तथा 6 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन से संबंधित हैं। प्रक्षेपणों का विवरण अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 उपग्रह परियोजनाओं में किसी प्रकार की लागत वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि, चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 उपग्रहों के लिए क्रमशः 28 माह और 46 माह की समय-वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

आदित्य-एल1: परियोजना में समय-वृद्धि का कारण कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, कक्षा को निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) से लैग्रेंजियन बिंदु (L1) में बदलना रहा, जिसके चलते उपग्रह के विन्यास में बदलाव करना पड़ा। इसके अलावा, पेलोड के विकास में अधिक समय लगना तथा दीर्घ-अवधि वाले उपकरणों/सामग्रियों की खरीद में लगने वाला अतिरिक्त समय भी समय-वृद्धि के प्रमुख कारण रहे।

चंद्रयान-3: परियोजना में समय-वृद्धि चंद्रयान-2 विफलता विश्लेषण समिति द्वारा सुझाए गए सुधारों को शामिल करने के लिए प्रणालियों के पुनः विन्यास, कोविड-19 महामारी, नए विशेष परीक्षणों के संचालन तथा नए सेंसर के विकास के कारण हुई।

गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) तक स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा जनवरी 2019 में आधिकारिक स्वीकृति दी गई थी। इसके अंतर्गत समान विन्यास में दो मानव रहित मिशन और एक मानव सहित मिशन संचालित किए जाने का प्रावधान था। इस कार्यक्रम के लिए कुल ₹9,023 करोड़ के बजट को स्वीकृति दी गई थी तथा मानव सहित मिशन के प्रक्षेपण का लक्ष्य मई 2022 निर्धारित किया गया था।

हाल ही में अक्टूबर 2024 में गगनयान कार्यक्रम के दायरे में संशोधन किया गया, जिसके तहत मिशनों की संख्या तीन से बढ़ाकर

आठ कर दी गई। इसमें एक अतिरिक्त मानव रहित मिशन (G1) तथा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) के लिए चार अग्रदूत (प्रीकर्सर) मिशन शामिल किए गए हैं। संशोधित कार्यक्रम के लिए कुल बजट प्रावधान ₹20,193 करोड़ किया गया है। संशोधित स्वीकृति के अनुसार सभी गतिविधियां प्रगति पर हैं और पहले मानव सहित मिशन का लक्ष्य वर्ष 2027झ28 रखा गया है।

गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत इसरो नियोजित मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विभिन्न प्रणालियों का विकास और निर्माण कर रहा है। मानव उड़ान के लिए निर्धारित कड़े ह्यूमन रेटिंग मानकों को ध्यान में रखते हुए, मानव-रेटेड प्रक्षेपण यान (HLVM3) की संरचनाओं, सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम, क्रू मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम तथा पैराशूट आधारित अवरोह/धीमी गति प्रणाली के व्यापक परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। इसके अलावा, अत्यंत महत्वपूर्ण क्रू एस्केप सिस्टम के मोटरों का भी विकास कर लिया गया है और उनके स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। साथ ही, स्वदेशी पर्यावरण नियंत्रण एवं जीवन समर्थन प्रणाली के विकास का कार्य समानांतर रूप से प्रगति पर है।

प्रमुख अवसंरचनाएं जैसे ऑर्बिटल मॉड्यूल प्रिपरेशन फैसिलिटी, गगनयान कंट्रोल सेंटर तथा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा स्थापित की जा चुकी हैं। दूसरे लॉन्च पैड में आवश्यक संशोधन भी कर दिए गए हैं। टीवी-डी1 (TV-D1) और आईएडीटी-01 (IADT-01) जैसे अग्रदूत (प्रीकर्सर) मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। ग्राउंड ट्रैकिंग नेटवर्क, स्थलीय संचार लिंक तथा आईडीआरएसएस-1 (IDRSS-1) फीडर स्टेशनों की स्थापना कर ली गई है। क्रू मॉड्यूल रिकवरी योजना तथा इसके लिए तैनात किए जाने वाले संसाधनों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पहले मानव रहित मिशन (G1) के लिए HLVM3 के सभी चरण और क्रू एस्केप सिस्टम (CES) मोटर तैयार हैं। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल की प्रणालियाँ विकसित कर ली गई हैं तथा उनके संयोजन और एकीकरण (असेंबली एवं इंटीग्रेशन) का कार्य अंतिम चरण में है। पहला मानव सहित मिशन वर्ष 2027-28 में लक्षित है।

भारत ने वर्तमान में संचालित पीएसएलवी, जीएसएलवी और एलवीएम-3 प्रक्षेपण यानों के माध्यम से निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में 10 टन तक तथा भू-समकालिक ट्रांसफर कक्षा (GTO) में 4.2 टन तक के उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता के साथ अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। इन प्रक्षेपण यानों ने पृथ्वी अवलोकन, संचार, नेविगेशन और अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े उपग्रहों के लिए स्वतंत्र अंतरिक्ष पहुँच सुनिश्चित की है। विस्तारित अंतरिक्ष दृष्टि को पूरा करने हेतु प्रक्षेपण यान क्षमताओं को और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) के विकास को मंजूरी दी है, जो निम्न पृथ्वी कक्षा में 30 टन तक की अधिकतम पेलोड क्षमता प्रदान करेगा। अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकियों का भी विकास किया जा रहा है, जिसमें आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य NGLV शामिल है, जिसकी LEO में 14 टन पेलोड क्षमता होगी। इसके अतिरिक्त, एक पंखयुक्त बॉडी अपर स्टेज का भी विकास किया जा रहा है, जो कक्षा से पृथ्वी पर वापस लौटेगा और स्वचालित रूप से रनवे पर उतरने में सक्षम होगा।

अधिक शक्तिशाली और अधिक दक्ष प्रोपल्शन प्रणालियों के विकास के संबंध में, इसरो ने एलवीएम-3 प्रक्षेपण यान में शामिल किए जाने हेतु उच्च-थ्रस्ट (2000 'ठ) अर्ध-क्रायोजेनिक इंजन के विकास का कार्य शुरू किया है। इसके साथ ही, नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) के लिए उच्च-थ्रस्ट इंजन हेतु एक पर्यावरण-अनुकूल मीथेन आधारित प्रोपल्शन प्रणाली की भी परिकल्पना की जा रही है, जिससे प्रस्तावित मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए प्रक्षेपण यान की प्रौद्योगिकीय तत्परता सुनिश्चित की जा सके। इनके अतिरिक्त, ड्यूल-फ्यूल स्क्रैमजेट इंजन की दिशा में एक एयर-ब्रीदिंग प्रोपल्शन प्रणाली का विकास भी प्रगति पर है।

सरकार ने अंतरिक्ष विभाग की महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। सरकार की स्पेस विजन 2047 के अंतर्गत वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना तथा वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है।

डब्लूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में विशेषज्ञों ने अश्वगंधा के भविष्य की रूपरेखा तैयार की

(जीएनएस)।

आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण रसायन जड़ी बूटियों में से एक अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा) ने दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन, 2025 में आयोजित एक उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र बना, जिसने साक्ष्य-आधारित वैश्विक संवाद के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा को आगे बढ़ाने में भारत के नेतृत्व की पुष्टि की।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र (डब्ल्यूएचओ-जीटीएमसी) द्वारा 'अश्वगंधाः पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक प्रभाव तक - अग्रणी वैश्विक विशेषज्ञों का दृष्टिकोण' शीर्षक से एक सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने प्रमुख वैश्विक विशेषज्ञों, नियामकों, शोधकर्ताओं एवं नीति निमार्ताओं को अश्वगंधा के आसपास विकसित हो रहे वैज्ञानिक, नियामकीय और सुरक्षा परिदृश्य पर विचार-विमर्श के लिए एकत्रित किया।

अश्वगंधा अपनी अनुकूलनीय, स्नायु सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा गुणों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर मान्यता प्राप्त कर रहा है। इस पर हुई चर्चा ने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों एवं समकालीन वैज्ञानिक सत्यापन के बीच के पुल को मजबूती प्रदान की। विशेषज्ञों ने इसके समर्थन के लिए कठोर पूर्व-नैदानिक एवं नैदानिक अनुसंधान, सुरक्षा मूल्यांकन, औषधि सतर्कता एवं मानकीकरण के महत्व पर बल दिया।

इस सत्र का संचालन विश्व अश्वगंधा परिषद के सचिव डॉ. जे.बी. गुप्ता ने किया जिसमें अग्रणी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने मुख्य प्रस्तुतियां दी। अमेरिकन हर्बल फामाकोपिया के डॉ. रॉय अप्टन ने पहचान, गुणवत्ता परीक्षण एवं चिकित्सीय अनुप्रयोगों के लिए वैश्विक मानकों पर प्रकाश डाला। सुश्री मारी ल्यरा, खाद्य एवं पशु आहार विभाग की प्रमुख, मेडफाइल्स लिमिटेड, फिनलैंड ने यूरोप के नियामक परिवेश और अश्वगंधा की बढ़ती स्वीकार्यता पर अपने विचारों को साझा किया। डॉ. इखलास खान, निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक उत्पाद अनुसंधान केंद्र, मिसिसिपी विश्वविद्यालय ने नियामक निर्णय लेने हेतु कार्यप्रणाली की सटीकता एवं ठोस साक्ष्यों की आवश्यकता पर बल दिया। डब्ल्यूएचओ-जीटीएमसी की डॉ. गीता कृष्णन ने अश्वगंधा को वैश्विक स्तर पर अपनाने में वादे एवं सतर्कता के बीच संतुलन पर प्रकाश डाला।

एक संवादात्मक पैनल चर्चा में विशेषज्ञों के बीच मानकों में सामंजस्य स्थापित करने, प्रभावकारिता की पुनरावृत्ति सुनिश्चित करने एवं साक्ष्य-आधारित अश्वगंधा सूत्रीकरण को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर खुलकर विचार-विमर्श हुआ। सत्र का समापन पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हुए अश्वगंधा को पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल संरचना में स्थापित करने के लिए निरंतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर आम सहमति के साथ हुआ।

विचार-विमर्श में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप, सुरक्षित, वैज्ञानिक एवं चिरस्थायी उपायों से पारंपरिक चिकित्सा को समकालीन स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करने की बढ़ती वैश्विक प्रतिबद्धता परिलक्षित हुई।

विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन पारंपरिक, पूरक एवं एकीकृत चिकित्सा पर संवाद, सहयोग और नीतिगत संरेखण के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें साक्ष्य, सुरक्षा एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जियो पारसी योजना की पारसी समुदाय ने व्यासपक सराहना की

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक पारसी समुदाय (जोरोस्ट्रियन) की आबादी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1941 में 1,14,000 से घटकर वर्ष 2011 में 57,264 रह गई है। पारसी समुदाय की घटती संख्या को रोकने के लिए सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से वर्ष 2013-14 में जियो पारसी योजना शुरू की थी। इस योजना के तीन घटक हैं:

i) चिकित्सा सहायता झ बांझपन, गर्भावस्था और नवजात शिशु संबंधी जटिलताओं के उपचार के लिए पारसी दंपतियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना; यह सहायता 30 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पारसी दंपतियों के लिए उपलब्ध है।

ii) समुदाय स्वास्थ्य - पारसी

दंपतियों को बच्चों और आश्रित सदस्यों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना; यह सहायता उन पारसी दंपतियों के लिए उपलब्ध है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 15 लाख रुपये तक है।

iii) प्रचार-प्रसार - योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

इस योजना के तहत सहायता राशि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अन्य सत्यापन के बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को जारी की जा रही है।

पिछले 5 वर्षों (अर्थात 2020-21 से 2024-25) के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 17.64 करोड़ रुपये का व्यय हुआ और 232 शिशुओं का जन्म हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) ने वर्ष 2025 के दौरान इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया था। आईआईपीएस की रिपोर्ट के अनुसार यह योजना लक्षित जनसंख्या तक पहुंचने में काफी हद तक सफल रही है और पारसी समुदाय ने इस योजना की उपयोगिता के बारे में लगभग सर्वसम्मत स्वीकृति दी थी।

इस योजना को वित्त आयोग के अगले सत्र के दौरान जारी रखने पर विचार किया जा रहा है।

यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

व्यापक सांस्कृतिक प्रसार और राजस्व सृजन के लिए प्रसार भारती ने कंटेंट सिंडिकेशन फ्रेमवर्क की शुरूआत की

(जीएनएस)।

प्रसार भारती ने सांस्कृतिक प्रचार-प्रसार और सामग्री के मुद्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने सार्वजनिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए सामग्री सिंडिकेशन नीति, 2025 का मसौदा तैयार किया है। यह मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रसार भारती की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

मीडिया जगत के प्रमुख हितधारकों के साथ एक सुनियोजित उद्योग परामर्श आयोजित किया गया। इनमें ओटीटी प्लेटफॉर्म, लीनियर टीवी प्रसारक, रेडियो नेटवर्क, दूरसंचार कंपनियां, आईपीटीवी ऑपरेटर और कंटेंट एग्रीगेटर शामिल हैं।

इस नीति का उद्देश्य दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित सामग्री, संग्रहित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सामग्री, और लाइव कवरेज (सरकारी कार्यक्रम, त्योहार, खेल आदि) से आय अर्जित करना है। इसमें प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित डिजिटल-फर्स्ट सामग्री को भी ध्यान में रखा गया है।

इसके अलावा मसौदा नीति में प्रसार भारती के स्वामित्व वाली कमीशन प्राप्त, सह-निर्मित, लाइसेंस प्राप्त और अन्य सामग्री के मुद्रीकरण का प्रस्ताव है। कंटेंट सिंडिकेशन नीति के मसौदे में प्रसार भारती की सामग्री की पहुंच का विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

इसमें लचीले लाइसेंसिंग मॉडल जैसे कि फ्लैट शुल्क, राजस्व साझाकरण, राजस्व साझाकरण के साथ न्यूनतम गारंटी आदि का प्रावधान है।

यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने बुधवार को लोकसभा में श्री सेल्वगनापति टीएम द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में उपलब्ध कराई।

ओटीटी क्षेत्र, भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक सांस्कृतिक पहुंच के प्रमुख चालक के रूप में उभर रहा है

वीडियो सदस्यता (सब्सक्रिप्शन) से होने वाली आय 2024 में 11% बढ़कर 9,200 करोड़ रुपये तक पहुंची

प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के शुरू होने के पहले वर्ष में ही 80 लाख उपयोगकर्ता हुए

(जीएनएस)।

ओवर-द-टॉप (ओटीटी) क्षेत्र ने भारतीय कहानियों, रचनात्मक प्रतिभा, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्र फिल्म निर्माण तक वैश्विक पहुंच को सक्षम बनाकर भारत की सॉफ्ट पावर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उद्योग जगत के अनुमानों (एफ आई सी सी आई-ईवाई मीडिया और मनोरंजन उद्योग रिपोर्ट 2025) के अनुसार, वीडियो सब्सक्रिप्शन से होने वाली आय 2024 में 11% की दर से बढ़कर 9,200 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। अनुमान है कि ओटीटी पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री के लिए भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या 9.5 से 11.8 करोड़ के बीच है।

लोक प्रसारक प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने दूरदर्शन और आकाशवाणी

सुलभ बनाकर इस पहुंच को और मजबूत किया है।

वेव्स ओटीटी ने उभरते फिल्म निमार्ताओं और रचनाकारों को समर्थन देने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। ये उन्हें विविध वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित के समृद्ध संग्रह, क्षेत्रीय कलाओं, वृत्तचित्रों, शास्त्रीय संगीत, साहित्य-आधारित कार्यक्रमों और बहुभाषी सामग्री को विश्वव्यापी दर्शकों के लिए वितरण मंच प्रदान करता है।

वेव्स ओटीटी मुख्य रूप से एक सदस्यता-मुक्त सार्वजनिक सेवा मंच है और यह सदस्यता-आधारित मॉडल पर काम नहीं करता है। विज्ञापन इसकी आय का मुख्य स्रोत है। इसका उद्देश्य भारत और विश्व स्तर पर सार्वजनिक प्रसारण सामग्री तक सभी की पहुंच को सुलभ बनाना है।

यह प्लेटफॉर्म वर्तमान में विकास और विस्तार के चरण में है और इसके अंतरराष्ट्रीय उपयोगकताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आय के स्रोत धीरे-धीरे विकसित किए जा रहे हैं।

इसके आरम्भ होने के पहले वर्ष में ही 80 लाख से अधिक डाउनलोड के साथ उपयोगकर्ता वृद्धि में उल्लेखनीय उछाल आया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुभाषी भारतीय सामग्री और सार्वजनिक सेवा मीडिया की बढ़ती मांग को दशार्ता है।

सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 (2023 में संशोधित) जोड़ी गई नई धारा 7(1बी)(ए) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3) के अंतर्गत केंद्र सरकार को चोरी की गई फिल्म सामग्री जारी करने वाले मध्यस्थों पर कार्रवाई करने का अधिकार देती है।

यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज लोकसभा में श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई मादम द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में प्रस्तुत की।

आईएमडी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पूवार्नुमान मॉडल की सटीकता में काफी सुधार हुआ

(जीएनएस)।

आईएमडी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पूवार्नुमान मॉडल की सटीकता में काफी सुधार हुआ है; हालांकि, 100% सटीकता के साथ पूवार्नुमान करना संभव नहीं है। मौसम विज्ञान उप-मंडलों में मॉनसूनी भारी बारिश का 24 घंटे (1 दिन) पहले पता लगाने का स्किल स्कोर 2024 में 85% है। फिलहाल, आईएमडी के भारी बारिश के पूवार्नुमान की सटीकता, जिसे सही चेतावनियों के प्रतिशत के तौर पर मापा जाता है, एक से पांच दिन के लीड टाइम के लिए क्रमशः 85%, 73%, 67%, 63% और 58% है। कुल मिलाकर, 2014 की तुलना में 2023-2024 में देश भर में भारी बारिश की घटनाओं के लिए पूवार्नुमान की सटीकता में करीब 40% का सुधार हुआ है।

आईएमडी भारी बारिश की मात्रा और भारी बारिश होने वाले क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारी बारिश के प्रभाव-आधारित पूवार्नुमान और जोखिम-आधारित पूवार्नुमान शुरूआती चेतावनी जारी करता है। चेतावनी मौसम विज्ञान उप-मंडल और जिला स्तर पर जारी की जाती है, जो क्रमशः 7 और 5 दिनों तक मान्य होती है। हर तीन घंटे में नाउकास्टिंग भी होती है, जिसमें भारी बारिश के

लिए अगले तीन घंटों की वैधता होती है।

आईएमडी का अत्याधुनिक पूवार्नुमान सिस्टम देश के सभी जिलों में पूरी तरह से काम कर रहा है। हाई-रिजॉल्यूशन मॉडल और ऋक्ष सिस्टम देश के सभी जिलों को कवर करते हैं। डॉप्लर मौसम रडार (डीडब्ल्यूआर) नेटवर्क की बात करें तो, अभी पूरे भारत में 47 डीडब्ल्यूआर काम कर रहे हैं, जिससे देश का 87% कुल क्षेत्र रडार कवरेज में आता है। आने वाले सालों में, एमओईएस के मिशन मौसम के अंतर्गत देश के बाकी बचे खाली वाले क्षेत्र को कवर करने, अतिरेकता देने और डीडब्ल्यूआर नेटवर्क में पुराने रडार को बदलने के लिए जरूरत के हिसाब से डीडब्ल्यूआर लगाए जाएंगे। मंत्रालय मौसम के पूवार्नुमान में अधिक सटीकता हासिल करने के लिए अवलोकन क्षमताओं और आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त, आईएमडी ने देश में अवलोकन, डेटा एक्सचेंज, मॉनिटरिंग और एनालिसिस, पूवार्नुमान और चेतावनी सेवाओं के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया है, जिसमें संवेदनशील जिले भी शामिल हैं।

ऐसे हाई-रिजॉल्यूशन मॉडल के लिए गणितीय सहयोग देने और उन्हें सामान्य रूप से त्वरित समय पर चलाने के लिए, कंप्यूटिंग सुविधाओं (अरुणिका और अर्का) को भी बहुत बढ़ाया गया है, जिससे भारी मात्रा में डेटा को एकीकृत किया जा सके और मीसोस्केल, क्षेत्रीय और वैश्विक मॉडल को हाई रिजॉल्यूशन पर चलाया जा सके। इसके साथ ही, हाल ही में, एमओईएस ने भारत को "मौसम के लिए तैयार और क्लाइमेट-स्मार्ट" देश बनाने के लिए एक नई केंद्रीय योजना, "मिशन मौसम" लॉन्च की है। असुरक्षित आबादी तक चेतावनियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हाल ही में लॉन्च की गई भारत पूवार्नुमान प्रणाली (भारतएफएस) मुख्य रूप से कम समय और मध्यम अवधि के मौसम के पूवार्नुमान को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है।

पूवार्नुमान में सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अधिक अवलोकन और गणितीय मौसम पूवार्नुमान मॉडल को शामिल किया जाता है। पारंपरिक (सतह,

वामपंथी उग्रवाद: राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार कमी

(जीएनएस)।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सरकारों के अधीन हैं। हालांकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। वामपंथी उग्रवाद के खतरे से समग्र रूप से निपटने के लिए, वर्ष 2015 में "वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" को मंजूरी दी गई थी। इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी हस्तक्षेपों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और अधिकारों को सुनिश्चित करने आदि सहित बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार कमी आई है और इसका भौगोलिक प्रसार सीमित हुआ है। वामपंथी उग्रवाद, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है, हाल के समय में काफी हद तक कम हो गया है और अब केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया है।

नक्सलवादी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) द्वारा की गई हिंसा की घटनाएं 2010 में 1936 के उच्च स्तर से घटकर 2025 में 222 रह गईं, जो 89% की गिरावट है। इसके परिणामस्वरूप नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतें भी 2010 में 1005 के उच्च स्तर से घटकर 2025 में 95 रह गईं, जो 91% की गिरावट है। नक्सलवादी उग्रवादियो प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई 2021 में 70, अप्रैल 2024 में 38, अप्रैल 2025 में 18 और अक्टूबर 2025 में केवल 11 रह गई है। अब केवल 3 जिले ही सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की श्रेणी में आते हैं। सरकार द्वारा आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से नक्सलवाद के मूल कारण का समाधान हुआ है। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति, साथ ही बुनियादी ढांचे में निवेश ने सार्वजनिक/निजी निवेश में वृद्धि सहित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है।

सुरक्षा के मोर्चे पर, भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) बटालियन, हेलीकॉप्टर सहायता, शिविर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी साझा करना, किलेबंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण और भारतीय रिजर्व बटालियनों को मंजूरी देना आदि प्रदान करती है।

राज्यों की क्षमता निर्माण के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक सुरक्षा बलों के परिचालन व्यय और प्रशिक्षण आवश्यकताओं, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी कार्यकताओं के पुनर्वास, उग्रवादी हिंसा में मारे गए नागरिकों और शहीद सुरक्षा बल कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि आदि के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत उग्रवादी हिंसा से प्रभावित राज्यों को लगभग 1,643 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के तहत राज्य के विशेष बलों, राज्य खुफिया शाखाओं (एसआईबी), जिला पुलिस को मजबूत करने और किलेबंद पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) के निर्माण के लिए उग्रवादी हिंसा से प्रभावित राज्यों को 1757 करोड़ रुपये के कार्यों की मंजूरी दी गई है।

वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार और राज्य सरकारों ने व्यापक आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियां तैयार की हैं। भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत 'आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास' नीति के माध्यम से राज्यों को इस प्रयास में सहयोग प्रदान करती है। भारत सरकार एसआरई योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवादियों से प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के अलावा, उच्च श्रेणी के वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) के कैडरों के लिए 5 लाख रुपये और अन्य एलडब्ल्यूई कैडरों के लिए 2.5 लाख रुपये का तत्काल अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत हथियार और गोला-बारूद आत्मसमर्पण करने पर प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। साथ ही, तीन वर्षों के लिए 10,000 रुपये के मासिक वजीफे के साथ उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान है। प्रभावित राज्यों ने अपनी आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियों को आकर्षक और समकालीन बनाने के लिए उनमें संशोधन किया हैं।

राज्यों द्वारा अपने पुलिस बलों को सुसज्जित और आधुनिक बनाने के प्रयासों को "राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस आधुनिकीकरण हेतु सहायता" योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों को हथियारों, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, प्रशिक्षण, पुलिस स्टेशनों के निर्माण, गतिशीलता, पुलिस आवास और अन्य पुलिस अवसंरचना आदि के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से सहायता प्रदान की जाती है।

वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) की वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करने और सी पी आई (माओवादी) तथा उसके वित्तीय समर्थकों के बीच सांठगांठ का पदार्फाश करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एलडब्ल्यूई को मिलने वाले धन और अन्य संसाधनों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए, राज्य पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न माध्यमों से समन्वित कार्रवाई कर रही है।

भारत सरकार का सुरक्षा अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण रहा है। पिछले दशक में 656 किलेबंद पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा, पिछले छह वर्षों में नक्सलवादी उग्रवादियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में 377 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं।

विकास के मोर्चे पर, भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के अलावा, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए कई विशिष्ट पहलें की गई हैं, जिनमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 से शुरू हुए इनमें से कुछ कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है :

ड्ड सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी) और सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) नामक 2 एलडब्ल्यूई विशिष्ट योजनाओं के तहत 8301 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है।

ड्ड बिजली संकट से प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 6,775 टावर चालू किए गए हैं।

ड्ड कौशल विकास के लिए 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 5 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) कार्यरत हैं।

ड्ड आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 95 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किए गए हैं।

ड्ड वित्तीय समावेशन के लिए, डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं से लैस 4,262 डाकघर खोले हैं। अधिकांश एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में 719 बैंक शाखाएं और 204 एटीएम खोले गए हैं।

ड्ड विकास को और गति देने के लिए, विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत अधिकांश एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में सार्वजनिक अवसंरचना की महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कुल लगभग 1,576 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

वर्ष 2020-2025 की अवधि के दौरान देश में नागरिकों की मृत्यु और सुरक्षा बलों के शहीदों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

भारत सरकार अपने देश से वामपंथी उग्रवाद के पूर्ण उन्मूलन और वामपंथी उग्रवाद से मुक्त क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने 11 से 13 दिसंबर 2025 तक ट्यूनीशिया के ट्यूनिस में आयोजित ' अफ्रीका फूड 2025' में भाग लिया

वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना: खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने ट्यूनिस में आयोजित अफ्रीका फूड 2025 सम्मेलन में उद्योग जगत के दिग्गजों और सरकारी हितधारकों के साथ व्यापार, निवेश और खाद्य सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्तालाप किया

(जीएनएस)।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने 11 से 13 दिसंबर 2025 तक ट्यूनीशिया के ट्यूनिस में आयोजित ' अफ्रीका फूड 2025' में भाग लिया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप सचिव

श्री विवेक कुमार सिंह और उप सचिव श्री अरुणव सेन गुप्ता ने किया।

इस आयोजन के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने इंडिया पवेलियन में उद्योग जगत के हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से वार्तालाप करते हुए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने ट्यूनीशिया सरकार के प्रतिनिधियों और विभिन्न औद्योगिक संघों के साथ भी द्विपक्षीय सहयोग और बाजार पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से बातचीत की।

इस यात्रा के अंतर्गत, प्रतिनिधिमंडल ने ट्यूनिस में एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का दौरा किया और बहुमूल्य जानकारी और प्रतिक्रिया साझा की, जिससे खाद्य सुरक्षा बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को मजबूत करने पर चर्चा में योगदान मिला।

यह भागीदारी खाद्य सुरक्षा एवं प्रसंस्करण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, व्यापार संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का समर्थन करने के लिए खाद्य एवं खाद्य प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निरंतर प्रयासों को दशार्ती है।

खाड़ी देशों में विदेशी तैनाती पर भारतीय तटरक्षक बल का जहाज सार्थक एक रणनीतिक यात्रा में ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पहुंचा

(जीएनएस)।

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) का अपतटीय गश्ती पोत सार्थक ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पहुंच गया है। रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यह गहरे पानी का बंदरगाह भारत को ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ने वाला एक सीधा व सुरक्षित समुद्री मार्ग उपलब्ध कराता है। यह पोत 16 से 19 दिसंबर, 2025 तक चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर ईरान में रहेगा।

चाबहार बंदरगाह पर भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के इस जहाज की यह पहली यात्रा है, जो क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी को स्पष्ट रूप से दशार्ती है। यह दौरा अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सुरक्षित एवं भरोसेमंद आपूर्ति लाइनों को सुदृढ़ करने की भारत की क्षमता को भी रेखांकित करती है।

भारतीय तटरक्षक बल का जहाज सार्थक बंदरगाह पर प्रवास के दौरान ईरानी नौसेना तथा ईरान की अन्य

समुद्री एजेंसियों के साथ विभिन्न पेशेवर एवं सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेगा। इनमें शिष्टाचार भेंट, कार्य संबंधी संवाद व विचार-विमर्श शामिल हैं, जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संस्थागत संबंधों को सुदृढ़ करना तथा समुद्री सुरक्षा, सहयोग एवं आपसी समझ को और अधिक गहरा करना है।

बंदरगाह के प्रमुख आकर्षणों में समुद्री खोज एवं बचाव (एसएआर), समुद्री कानून प्रवर्तन (एमएलई) और समुद्री प्रदूषण रोधी कार्रवाई (एमपीआर) पर केंद्रित संयुक्त प्रशिक्षण गतिविधियां शामिल होंगी। चाबहार बंदरगाह में तेल रिसाव और खतरनाक तथा हानिकारक पदार्थों (एचएनएस) के रिसाव से निपटने पर आधारित समुद्री प्रदूषण रोधी प्रतिक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे दोनों पक्षों के समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र की क्षमता प्रदर्शित हो सके। इसके अतिरिक्त, एमआरसीसी-से-एमआरसीसी समन्वय अभ्यास, एक टेबल-टॉप अभ्यास तथा संयुक्त दौरा, बोर्डिंग, तलाशी व जब्ती (वीबीएसएस) अभ्यास आयोजित किए जाएंगे, जो दोनों देशों के बीच सहभागिता, आपसी समन्वय एवं परिचालन तत्परता को और अधिक सुदृढ़ करेंगे।

पैशेवर गतिविधियों के अतिरिक्त, इस यात्रा के दौरान खेल प्रतियोगिताओं के अलावा एक बीच वॉकथॉन भी आयोजित किया जाएगा, जिनमें राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेट सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जरुरतमदों को लगातार कंबल वितरित करें। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था रहे और सभी रैन बसेरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी

- मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और नगर निकायों के साथ समीक्षा
- निरीक्षण और समुचित व्यवस्था करें अधिकारी, कोई बाहर सोता न मिले
- सड़कों, गलियों, हाईवे से लेकर एक्सप्रेस-वे तक सुरक्षा इंतजाम रहें चाक-चौबंद
- जनजीवन, यातायात और निराश्रितों की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही
- मंडलायुक्त, आईजी, डीएम, पुलिस, ट्रैफिक बल, नगर निकाय को बेहतर प्रबंधन की जिम्मेदारी

लखनऊ: (जीएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ती ठंड और कोहरे को लेकर अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और नगर निकायों को निर्देश दिया है कि कोई व्यक्ति खुले में सोता न मिले। अधिकारी सभी जगह निरीक्षण करें और शीतलहर में निराश्रितों की भी समुचित व्यवस्था करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जगह रैन बसेरा में अलाव और हीटर की पर्याप्त व्यवस्था हो। रेन बसेरों का निरंतर निरीक्षण हो और वहां पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो। उन्होंने निराश्रितों और जरूरतमंदों को हर संभव राहत और मदद प्रदान करने के निर्देश देने के साथ ही कहा कि अधिकारी फील्ड में सतर्क रहें और देखें कि कोई खुले में ना सोए। निराश्रितों को रैन बसेरों तक ले जाया जाए और जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जरुरतमदों को लगातार कंबल वितरित करें। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था रहे और सभी रैन बसेरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। गोशालों में अलाव के साथ गोवंश को ठंढ से बचाने की समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने घने कोहरे को लेकर सभी मंडलायुक्त, आईजी, जिलाधिकारियों, कप्तानों और ट्रैफिक पुलिस बलों को दिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घने कोहरे में प्रबंधन ठीक से हो और सड़कों व गलियों की लाइट को लगातार चेक करें। अगर लाइट खराब है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। डार्क स्पॉट को चिन्हित कर समुचित कदम उठाए जाएं और राजमार्गों सड़कों पर जरूरत के हिसाब से रिफ्लेक्टर बनाए जाए।

उन्होंने अधिकारियों को एनएचएआई व स्टेट हाईवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर व्यवस्था सही करने का निर्देश दिया और एक्सप्रेस-वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने व हर ब्लैक स्पॉट पर तैनात टीमें रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि खराब विजिबिलिटी पर एक्सप्रेस-वे पर यातायात का प्रबंधन सुनिश्चित करें और सुरक्षित यात्रा के लिए जनता 'एडवाइजरी' का सख्ती से पालन करे। एक्सप्रेस-वे पर सातों दिन 24 घंटे क्रेन और एंबुलेंस रहें।

टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर के माध्यम से चालकों को कोहरे की स्थिति की चेतावनी दी जाए। कोहरे में 'ओवरस्पीडिंग' करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इमरजेंसी इंडिकेटर्स को चालू रखने और आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोहरा होने के बाद लोगों से एक्सप्रेस-वे पर बार-बार लेन बदलने से बचने और ओवरटेकिंग बिल्कुल न करने को कहा है। यदि कोहरा बहुत घना हो, तो रिस्क न लें। अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगवाएं।

धुंध और कोहरे के दौरान 'ट्रैवल गाइडलाइन'

धुंध के दौरान वाहन की गति निर्धारित सीमा से कम रखें।

वाहन की फॉग लाइट का प्रयोग करें और लो-बीम पर हेडलाइट रखें।

इमरजेंसी इंडिकेटर्स को चालू रखें

आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें

एक्सप्रेस-वे पर बार-बार लेन बदलने से बचें

ओवरटेकिंग बिल्कुल न करें

यदि कोहरा बहुत घना हो, तो रिस्क न लें

अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगवाएं

उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का उपयोग

(जीएनएस)।

परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), जो परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) की एक इकाई है, यह आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (एएनडीयूएटी), कुमर्गंज, अयोध्या के सहयोग से किरणन (रेडिएशन) से उत्पन्न उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) प्रजनन पद्धति का उपयोग करके स्थानीय सुगंधित धान किस्म ह्यकाला नमकह्ल के सुधार के कार्य में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। काला नमक धान सुधार पर अनुसंधान एवं विकास कार्य में प्रदेश के छह (6) विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) अर्थात सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुरझक एवं क्क और बलरामपुर स्टेशन शामिल हैं, जिनसे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के किसानों को काफी लाभ होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि विभाग के दस (10) क्षेत्रीय अनुकूलन परीक्षण एवं प्रदर्शन स्टेशन (आर ए टी डी एस) की पहचान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण-उन्नत (रेडिएशन-इम्प्रूव्ड) धान की उत्परिवर्तित अभिजन्य रेखाओं (म्यूटेंट डेरिवेटिव्स) के परीक्षण हेतू की गई है। इसके अतिरिक्त, विकिरण-प्रेरित गेहूँ और भिन्डी (ओकरा) सुधार कार्यक्रम रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (एयरलबीसीएयू), झांसी तथा एएनडीयूएटी),अयोध्या के सहयोग से चलाया जा रहा है।

भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कानपुर, आगे चलकर इसे नियमित रूप से राष्ट्रीय मूल्यांकन परीक्षणों में बी ए आर सी द्वारा विकसित उत्परिवर्तित रेखाओं का मूल्यांकन करता है।

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए राई (सरसों) और गेहूँ की फसल के लिए उपज मूल्यांकन परीक्षण, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (बी यू ए टी), बांदा के सहयोग से चलाए जा रहे हैं।

डी ए यू /नाभिकीय विज्ञानों में अनुसंधान बोर्ड (बी आर एन एस) ने मसूर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के सुधार हेतु विकिरण-प्रेरित उत्परिवर्तन (रेडिएशन-इंड्यूस्ड म्यूटाजेनेसिस) पर आधारित एक शोध परियोजना के लिए आइसीएआर -आई आई पी आर, कानपुर को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

बी ए आर सी की मूंगफली किस्म ळक्ष्37अ का चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मैनपुरी, के सहयोग से मूल्यांकन कर इसे उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है।

ट्रॉम्बे अलसी किस्म ळछ 99, जो बी ए आर सी द्वारा विकसित पहली भारतीय खाद्य तेल की किस्म है। यह कम लिनोलेनिक एसिड सामग्री, उच्च बीज उपज तथा उच्च तेल उपज है जिसे उत्तर प्रदेश के लिए व्यावसायिक खेती हेतु जारी किया गया है। इन बीजों को न्यूक्लियस, ब्रिडर, फाउंडेशन तथा प्रमाणित बीज के रूप में व्यावसायिक खेती के विभिन्न चरणों में वगीर्कृत किया जाता है।ट्रॉम्बे फसल किस्मों के बीज विभिन्न राज्यों के किसानों को संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से उपलब्ध कराए जाते हैं।

ळछ-99 के 10.0 किलोग्राम न्यूक्लियस बीज आई आई पी आर , कानपुर को बीज उत्पादन एवं इसके जन प्रसार हेतु दिए गए थे। बी ए आर सी द्वारा मूंगफली किस्मों के ब्रिडर बीज विभिन्न एजेंसियों को प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध कराए गए हैं।

ट्रॉम्बे मूंगफली के ब्रिडर बीज उत्तर प्रदेश के सात जिलों को बी ए आर सी द्वारा विकसित फसल किस्मों के उपयोग को विस्तार देने हेतु प्रदान किए गए थे।

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में तीन ऐसी सुविधाएँ पहले से ही चालू हो चुकी हैं तथा मांग के आधार पर ये विकिरण प्रसंस्करण सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा उत्पाद नसबंदी हेतु एक ऐसी सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है।वर्तमान में विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के छात्र बी ए आर सी , मुंबई में परमाणु कृषि के विभिन्न पहलुओं पर शोध परियोजना कार्य करते हैं। सामान्य शोध हित के आधार पर यह केंद्र उत्तर प्रदेश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समझौता प्रपत्र तैयार करने की प्रक्रिया में भी हैं।

इसके अतिरिक्त, डी ए ई /बी आर एन एस ने राज्य में स्थित विभिन्न शोध केंद्रों में परमाणु कृषि पर शोध परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान किया है। जागरूकता एवं समझ बढ़ाने हेतु, विकिरण प्रौद्योगिकियों के लाभकारी उपयोग पर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ए एन डी यू ए टी), अयोध्या के छात्रों एवं फैकल्टी को व्याख्यान दिए गए, तथा भारतीय नाभिकीय सोसाइटी के तत्वावधान में लखनऊ के चार प्रमुख संस्थानों में कृषि, खाद्य, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सिम के दुरुपयोग और साइबर सुरक्षा के लिए मोबाइल उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी

दूरसंचार विभाग (डीओटी) संचार साथी पहल के तहत व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है और दूरसंचार से संबंधित धोखाधड़ी को रोक रहा है

(जीएनएस)।

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने आज लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 की उपधारा 42(3)(ई) के अनुसार, धोखाधड़ी, ठगी या प्रतिरूपण (किसी व्यक्ति का वेष बनाकर) के माध्यम से ग्राहक पहचान मॉड्यूल या अन्य दूरसंचार पहचानकर्ता प्राप्त करना एक अपराध है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ह्यपुलिसह्ल और ह्यसार्वजनिक व्यवस्थाह्ल राज्य के विषय हैं।

सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 की उपधारा 42(3)(सी) और उपधारा 42(3)(एफ) के तहत आवश्यक कानूनी प्रावधान किए हैं, जिसके तहत दूरसंचार पहचानकताओं के साथ छेड़छाड़ करना और जानबूझकर रेडियो उपकरण रखना, यह जानते हुए कि यह अनधिकृत या छेड़छाड़ किए गए दूरसंचार पहचानकताओं का उपयोग करता है, अपराध माना गया है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर विशिष्ट दूरसंचार उपकरण पहचान संख्या को हटाने, मिटाने, बदलने या उसमें हेरफेर करने या जानबूझकर दूरसंचार पहचानकर्ता या दूरसंचार उपकरण से संबंधित हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का उपयोग करने, उत्पादन करने, उसका व्यापार करने, उस पर नियंत्रण रखने या उसे अपने पास रखने से प्रतिबंधित करते हैं, यह जानते हुए कि इसे इस तरह से विन्यास किया गया है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने लाइसेंस की शर्तों के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे प्रत्येक उपभोक्ता को उपभोक्ता के रूप में नामांकित करने से पहले उसका पर्याप्त सत्यापन सुनिश्चित करें।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने एक नागरिक केंद्रित संचार साथी पोर्टल और ऐप विकसित किया है, जो अन्य बातों के साथ साथ नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है। दूरसंचार विभाग संचार साथी पहल के तहत व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है और दूरसंचार से संबंधित धोखाधड़ी को रोक रहा है। आईएमईआई सत्यापन से संबंधित व्याख्यात्मक वीडियो और इन्फोग्राफिक्स तैयार कर विभाग के सोशल मीडिया मंच पर अपलोड कर दिए गए हैं। विभाग ने संचार मित्र योजना भी शुरू की है, जिसके माध्यम से छात्र स्वयंसेवकों को नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और संचार साथी पोर्टल एवं ऐप के उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए शामिल किया गया है। उनकी भागीदारी खासकर स्थानीय भाषाओं में संचार के माध्यम से जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। उपरोक्त के अलावा, नागरिक संपर्क में बहुभाषी समाचार लेख और विज्ञापन, सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल स्क्रीन और होर्डिंग्स, टीवी और रेडियो संदेश, परिवहन विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा स्थानीय स्तर की गतिविधियां, टीएसपी के साथ एसएमएस अभियान और व्यापक सोशल मीडिया सामग्री शामिल हैं।

संचार साथी साइबर धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के संदिग्ध दुरुपयोग की रिपोर्ट करने में सभी नागरिकों द्वारा 'जन भागीदारी' में भी मदद करता है।

आईएनएएस 335 (ऑस्प्रे) को कमीशन किया गया

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना के दूसरे वायु स्क्वाड्रन आईएनएएस 335 ह्यद ऑस्प्रेह्न को 17 दिसंबर 2025 को गोवा स्थित आईएनएस हंसा में आयोजित एक भव्य समारोह में कमीशन किया गया। यह एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों का संचालन करता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर नौसेना प्रमुख (सीएनएस) एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मार्च, 2024 में केरल के कोच्चि में पहले एमएच-60आर नौसेना वायु स्क्वाड्रन के परिचालन में आने के बाद भारतीय नौसेना की वायु शक्ति के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक और मील का पत्थर है। समारोह में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी उपस्थित थे।

यूनिट के कमीशनिंग वारंट का वाचन कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन धीरेंद्र बिष्ट द्वारा किया गया। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र एनडब्ल्यूडब्ल्यूए की अध्यक्ष श्रीमती लैला स्वामीनाथन ने कमीशनिंग पट्टिका का विधिवत अनावरण किया। इस ऐतिहासिक अवसर को और भी स्मरणीय बनाने हेतु समारोह के दौरान पारंपरिक जल तोपों की भव्य सलामी दी गई।

इस कार्यक्रम में पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल राहुल विलास गोखले, गोवा नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग और फ्लैग ऑफिसर नेवल एविएशन रियर एडमिरल अजय डी. थियोफिलस की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके अतिरिक्त नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह (सेवानिवृत्त), नौसेना के कई वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व सैनिक एवं अन्य विशिष्ट अतिथि भी समारोह में उपस्थित थे।

एमएच-60आर सभी तरह के मौसम में दिन-रात के संचालन हेतु एक सक्षम व अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, जिसे पनडुब्बी रोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू), सतह रोधी युद्ध (एएसयूडब्ल्यू), खोज एवं बचाव (एसएआर), चिकित्सा निकासी (एमईडीईवीएसी) और समुद्री जहाजों के बीच आपूर्ति (वीआरटीआरईपी) जैसे विविध अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना की समग्र विमानन और परिचालन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

भारत-यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 के लिए भारतीय सेना का दल रवाना हुआ

(जीएनएस)।

भारत-यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन-क्क के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना का एक दल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के लिए रवाना हो गया है, जिसका आयोजन 18 से 30 दिसंबर 2025 तक अबू धाबी यूएई में किया जाना है।

भारतीय दल में 45 जवान शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से हैं। संयुक्त अरब अमीरात की थल सेना का दल, जिसकी संख्या लगभग समान है, 53वीं मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी वातावरण में संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय सेना और यूएई थल सेना के बीच अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे दोनों सेनाएं शांति स्थापना, आतंकवाद विरोधी और स्थिरता अभियानों के लिए एक साथ काम कर सकें।

दोनों देशों के सैनिक संयुक्त रूप से लगभग दो सप्ताह तक सामरिक अभ्यासों की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रशिक्षण लेंगे, जिसमें शहरी क्षेत्रों में लड़ाई, हेलीकॉप्टर आधारित अभियान और विस्तृत मिशन योजना शामिल हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में अभियानों के संचालन के लिए यूएएस और काउंटर-यूएएस तकनीकों का एकीकरण किया जाएगा।

27-28 अक्टूबर 2025 को यूएई थल सेना के कमांडर और 15-19 दिसंबर 2025 को यूएई राष्ट्रपति गार्ड के कमांडर की सफल यात्रा की गति को आगे बढ़ाते हुए, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन-क्क भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा।

डेजर्ट साइक्लोन-क्क अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी और सैन्य कूटनीति को रेखांकित करता है और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच पेशेवर संबंधों को और मजबूत करेगा। यह अभ्यास रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को बढ़ावा देगा और अंतर-संचालनीय क्षमताओं के विकास में योगदान देगा।

स्थानिक प्रौद्योगिकी विकसित भारत का एक मूलभूत स्तंभ है: डॉ. जितेंद्र सिंह

शासन, अवसंरचना और सेवा वितरण में परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन

विकसित भारत के लिए सरकार द्वारा भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का रणनीतिक राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग: डॉ. जितेंद्र सिंह

(जीएनएस)।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों को देश की विकास यात्रा का एक मूलभूत स्तंभ बताते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों ने अवसंरचना, कृषि, रक्षा, शहरी विकास, जलवायु कार्रवाई और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में योजना, कार्यान्वयन और सेवा वितरण के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

'भू-स्थानिक इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाना - भू-स्थानिक मिशन: विकसित भारत का एक प्रवर्तक' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत का भू-स्थानिक परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विनियमन से सशक्तिकरण की ओर एक निर्णायक बदलाव को दशार्ता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2021 के ऐतिहासिक भू-स्थानिक उदारीकरण सुधारों और उसके बाद लागू हुई राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 को रेखांकित करते हुए कहा कि इन उपायों ने उच्च-सटीकता वाले भू-स्थानिक डेटा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया है, नवाचार को बढ़ावा दिया है, उद्योग की भागीदारी को मजबूत किया है और विभिन्न क्षेत्रों में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को उल्लेखनीय रूप से विस्तारित किया है। उन्होंने कहा कि इसी गति को बनाए रखते हुए, विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप एक आधुनिक, सटीक और सुलभ राष्ट्रीय भू-स्थानिक अवसंरचना के निर्माण हेतु एक परिवर्तनकारी, समग्र सरकारी पहल के रूप में राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन का शुभारंभ किया गया है।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि स्मार्ट शहरों, सड़क और रेल अवसंरचना, सटीक कृषि, रसद अनुकूलन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई और अगली पीढ़ी की रक्षा तैयारियों जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं तेजी से विश्वसनीय, अंतरसंचालनीय और मजबूत भू-स्थानिक डेटा पर निर्भर करेंगी। सर्वे ऑफ इंडिया की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि देश के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद मानचित्रण संगठन के रूप में इसने भारत के भू-स्थानिक इकोसिस्टम को मजबूत करने और तकनीकी आधुनिकीकरण और संस्थागत नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने सर्वे ऑफ इंडिया की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इसमें संगठन की विरासत, तकनीकी विकास और भारत के विकास में इसके योगदान को दशार्या गया है।

आज नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भारतीय सर्वेक्षण विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, भारत और विदेश के विशेषज्ञ, उद्योग, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि एक साथ आए और राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों के अनुरूप भारत के भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए भारतीय सर्वेक्षण अधिकारी हितेश कुमार एस. मकवाना ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक ढाँचे के विकास में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नेतृत्व को रेखाँकित किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 1,100 से अधिक सतत परिचालन संदर्भ केंद्र (सीओआरएस) स्थापित किए हैं। इनका लाभ वर्तमान में 15,000 से अधिक उपयोगकर्ता उठा रहे हैं और राज्य और अनुसंधान सीओआरएस नेटवर्क को एक एकीकृत राष्ट्रीय भू-माप संदर्भ ढाँचे में एकीकृत किया जा रहा है।

मुख्य भाषण देते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने कहा कि भू-स्थानिक दिशानिर्देश 2021 और राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 ने नवाचार-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि आगामी राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन भू-माप आधुनिकीकरण, अंतरसंचालनीयता, भू-सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, ए आई और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने और कुशल भू-स्थानिक कार्यबल के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

कार्यशाला में राष्ट्रीय भू-भौतिकीय संदर्भ फ्रेम के आधुनिकीकरण, सीओआरएस अवसंरचना के सघनीकरण, भू-स्थानिक डेटा और मानचित्रण क्षमताओं को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय भू-स्थानिक डेटा रजिस्ट्री (एनजीडीआर) और एकीकृत भू-स्थानिक इंटरफेस (यूजीआई) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से डेटा तक निर्बाध पहुंच को सक्षम करने के लिए एक मजबूत भू-आईसीटी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित विचार-विमर्श किया गया।

कार्यशाला के दौरान यह घोषणा की गई कि सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) ने केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूगणित उत्कृष्टता केंद्र (यूएन-जीजीसीई) के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन में शामिल होकर वैश्विक भूगणित आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बल दिया है। कार्यशाला के साथ आयोजित एक प्रदर्शनी में एसओआई के प्रमुख उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया गया। इनमें भूगणितीय परिसंपत्ति रजिस्टर, भूगणितीय परिसंपत्ति मानचित्र, सीओआरएस सेवाएं और बहुभाषी राज्य मानचित्र शामिल हैं।

राष्ट्रीय कार्यशाला ने शासन को मजबूत करने, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाने और भारत को एक लचीले, समावेशी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए भू-स्थानिक डेटा और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।